International Journal of Trend in Scientific Research and Development (IJTSRD)
Volume 6 Issue 3, March-April 2022 Available Online: www.ijtsrd.com e-ISSN: 2456 – 6470

शिरोमणि अकाली दल की भारतीय राजनीति में भूमिका

Dr. Sukhwinder Singh

Assistant Professor, Department of Humanities & Social Sciences,
Govt. Engineering College, Jhalawar, Rajasthan, India

ABSTRACT

शिरोमणि अकाली दल (शिअद), जिसे अकाली दल के नाम से भी जाना जाता है, एक क्षेत्रीय राजनीतिक दल है, जैसा कि भारतीय निर्वाचन आयोग द्वारा अनुमोदित किया गया है। इसका जन आधार मुख्य रूप से पंजाब राज्य में है। अकाली दल सिख धर्म की राजनीतिक विचारधारा के साथ दक्षिण पंथी राजनीतिक स्थिति पर काम करता है। दूसरे शब्दों में, शिरोमणि अकाली दल के अस्तित्व का मूल दावा पंजाब और दुनिया भर के सिखों की मांगों को पूरा करने में है। एसएडी स्थिति में चरम दक्षिण पंथी है क्योंकि यह दावा करता है कि धर्म और राजनीति एक-दूसरे के पर्याय हैं और कोई दूसरे के बिना काम नहीं कर सकता है।

How to cite this paper: Dr. Sukhwinder Singh "Role of Shiromani Akali Dal in Indian Politics" Published in International Journal of Trend in Scientific Research and Development (ijtsrd), ISSN: 2456-6470, Volume-6 | Issue-3, April 2022, pp.1993-1998, URL: www.ijtsrd.com/papers/ijtsrd49890.pdf

IJTSRD49890

Copyright © 2022 by author (s) and International Journal of Trend in Scientific Research and Development Journal. This is an Open Access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution License (CC BY 4.0) (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0)

'शिरोमणि अकाली दल' नाम से कई राजनीतिक दल हैं। हालांकि, यहाँ देश की सबसे पुरानी क्षेत्रीय लोकतांत्रिक पार्टी को संदर्भित किया जा रहा है और यह सुखबीर सिंह बादल के नेतृत्व में निर्देशित है। कोई भ्रम न हो इसलिए अक्सर इस पार्टी को शिरोमणि अकाली दल (बादल) भी कहा जाता है। दिसंबर 1920 में सिख धार्मिक निकाय, शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक समिति के एक टास्क फोर्स के रूप में बनाये गये इस नये राजनीतिक दल ने पंजाब में सर्वाधिक जनसंख्या वाले सिख लोगों के हितों को कायम रखने का प्रमुख समर्थक होने का दावा किया है। अकाली दल के प्रथम अध्यक्ष के रूप में सरदार सरमुख सिंह चुब्बल के साथ बरडोली सत्याग्रह के दौरान अपनी सक्रिय भूमिका और वर्ष 1928 में साइमन कमीशन के खिलाफ भारी विरोध प्रदर्शन सहित पार्टी ने भारत की आजादी के संघर्ष में कुछ बहुत शानदार आख्यानों में भाग लिया। इसके अलावा, मास्टर तारा सिंह के नेतृत्व में अकाली दल के कार्यकर्ता सविनय अवज्ञा आंदोलन में सक्रिय रूप से शामिल थे और वर्ष 1940 में मुस्लिम लीग द्वारा पारित पाकिस्तान संकल्प के खिलाफ जोरदार विरोध प्रदर्शन किया क्योंकि पाकिस्तान के एक अलग राष्ट्र के निर्माण को पूर्ववर्ती पंजाब के लोगों के बीच संभावनाओं और सद्भावना के लिए हानिकारक माना गया था।.

मास्टर तारा सिंह के नेतृत्व में अकाली दल अपनी सफलता के चरम पर पहुँच गया। भारत द्वारा अपनी आजादी हासिल करने के बाद, एसएडी ने पंजाबी सुबा आंदोलन में भाग लिया, जिसका नेतृत्व संत फतेह सिंह ने किया था। अकालियों ने अविभाजित पूर्वी पंजाब से तोड़कर एक अलग राज्य बनाने की मांग की, जिसमें क्षेत्र के बहुसंख्यक पंजाबी भाषी लोग शामिल थे। विरोध इतने तीव्र थे कि भारत सरकार भूतपूर्व पूर्वी पंजाब की सीमाओं के पुनर्गठन की मांग पर सहमत हो गयी। अकाली दल के सत्ता में आने के साथ ही वर्ष 1966 में पंजाब का वर्तमान राज्य गठित हुआ था। लेकिन सरकार एसएडी के भीतर गुटवाद के कारण लंबे समय तक नहीं टिकी।

वर्तमान समय में अकाली दल भाजपा के साथ गठबंधन में है। पंजाब विधानसभा चुनाव, 2017 में अकाली दल को करारी हार का सामना करना पड़ा। जिसमें सत्तारूढ़ अकाली दल को सिर्फ 15 सीटें हासिल हुईं। अकाली दल विभिन्न सिख धार्मिक निकायों जैसे शिरोमणि गुरुद्वारा प्रभाखंड समिति और दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंध समिति को नियंत्रित करता है। धार्मिक, सांस्कृतिक और भाषाई अल्पसंख्यकों की रक्षा के प्रयासों के लिए पार्टी देश के साथ-साथ दुनिया भर में सिखों के बीच अत्यधिक सम्मानित है।

शिरोमणि अकाली दल का चुनाव चिन्ह तराजू है। तराजू चिन्ह दोनों पक्ष में बराबर के रूप में दिखाया गया है। यह आमतौर पर पार्टी के एक नीले-काले आयताकार ध्वज पर बना होता है। यह चिन्ह लोकप्रिय रूप से अदालत के कमरे के दृश्य में एक महिला जज, जिनकी आंखें काले फीते से बंधी रहती हैं, के द्वारा हाथ में तराजू पकड़े हुए प्रयोग किया जाता है। तराजू पूरी तरह से संतुलित होते हैं, यह सुझाव देने के लिए कि कानून संतुलित है, यह पक्षपाती नहीं है और कानून की नजर में सभी को न्याय दिया जाएगा।

एसएडी द्वारा इसके चुनाव चिह्न में एक समरूप प्रस्तुतीकरण हुआ है। एक पूरी तरह से संतुलित तराजू का चिह्न दर्शाता है कि जब लोकतांत्रिक अधिकारों और सिखों के हितों की बात आती है तब यह पक्षपातपूर्ण या पूर्वाग्रहित नहीं होता है। दूसरे शब्दों में, राष्ट्रीय अल्पसंख्यकों के आर्थिक और सामाजिक उत्थान तथा सिखों की लोकतान्त्रिक परम्पराओं और संस्कृति की सुरक्षा के लिए एसएडी द्वारा की गयीं मांगें पूरी तरह से संतुलित हैं एवं अतिशयोक्तिपूर्ण या नाजायज नहीं हैं। भारतीय संविधान की संवैधानिक संरचना में निर्देशित सामाजिक न्याय, बंधुता और धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांतों का सख्ती से पालन करते हुए शिरोमणि अकाली दल दुनिया भर में सिख समुदाय की रक्षा के लिए सभी संभव प्रयास करता है।

परिचय

शिरोमणि अकाली दल के नेता, जो पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारी भी हैं, नीचे सूचीबद्ध हैं:

- प्रकाश सिंह बादल, शिरोमणि अकाली दल के संरक्षक: वह पांच बार पंजाब राज्य के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। वह 1969 में मुख्यमंत्री बनने वाले सबसे कम उम्र के सदस्य थे। प्रकाश सिंह बादल अकाली दल के पूर्व अध्यक्ष रहे हैं। उन्हें पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के बाद देश का सबसे शक्तिशाली सिख नेता माना जाता है।
- सुखबीर सिंह बादल, एसएडी के अध्यक्ष: वह प्रकाश सिंह बादल के बेटे हैं और वर्तमान में पंजाब राज्य के उपमुख्यमंत्री हैं। वह वाजपेयी की अगुवाई वाले भाजपा शासन में केंद्रीय उद्योग राज्य मंत्री रह चुके हैं। वह शिरोमणि अकाली दल के एक बहुत ही प्रभावशाली नेता हैं, क्योंकि पार्टी की सभी नीतियां और योजनाएं उनके सक्षम मार्गदर्शन पर निर्भर करती हैं।
- हरसिमरत कौर बादल, सांसद: वह सुखबीर सिंह बादल की पत्नी हैं। वह 16 वीं लोकसभा में पंजाब के भटिंडा निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर रही हैं। वर्तमान में भारत सरकार के अंतर्गत खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री हैं
- परमजीत कौर गुलशन ,लोकसभा सांसद के रूप में 15वीं लोकसभा में पंजाब के फरीदकोट निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया है।
- रतन सिंह अजनाला ,ने भी लोकसभा सांसद के रूप में 15वीं लोकसभा में पंजाब के खडूर साहिब निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया है।
- शेर सिंह घुबाया,लोकसभा सांसद के रूप में 16 वीं लोकसभा में पंजाब के फिरोजपुर निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं।
- नरेश गुजराल, राज्य सभा सांसद हैं
- सुखदेव सिंह ढिंडसा, राज्य सभा सांसद और एसएडी के महासचिव
- बलविंदर सिंह भंडर, राज्य सभा सांसद
- रणजीत सिंह ब्रह्मपुरा, एसएडी के वरिष्ठ उपाध्यक्ष
- बलवंत सिंह रामूवालिया, वरिष्ठ उपाध्यक्ष और एसएडी के राष्ट्रीय प्रवक्ता
- अवतार सिंह हिट, एसएडी के महासचिव
- दलजीत सिंह चीमा, एसएडी के सचिव और प्रवक्ता[1]

पंजाब में एक क्षेत्रीय राजनीतिक दल के रूप में शिरोमणि अकाली दल की कई उपलब्धियां हैं। इनमें से कुछ नीचे सूचीबद्ध हैं:

- पार्टी के बैनर तले कई संगठन कार्य करते हैं, जिन्होंने स्वयं के प्रतिनिधित्व वाले वर्गों के हितों को पूरा करने में बड़ी सफलता प्राप्त की है। ये संगठन कुछ इस प्रकार हैं – आल इंडिया सिख स्टूडेंट्स फेडरेशन (एआईएसएसएफ) नामक छात्र विंग, बिक्रम सिंह मजीठिया के अंतर्गत युवा विंग और परमजीत कौर गुलशन के अंतर्गत महिला विंग। ये एसएडी की विचारधारा के तहत काम कर रहे सहायक लेकिन स्वायत्त संगठन हैं।
- अकाली दल विद्युत परियोजनाओं में हज़ारों करोड़ के निवेश और छोटी विद्युत उत्पादक इकाइयों में भी निवेश करके पंजाब को एक अधिशेष बिजली वाला राज्य बनाने के लिए प्रतिबद्ध है।
- एसएडी ने पिछली सरकारों की तुलना में राज्य के राजस्व में अधिक वृद्धि दर्ज की है और ऐसा इसलिए क्योंकि यह केंद्र से निधि इकट्ठा करने में कामयाब रही है।
- किसानों को बढ़ी हुई सिंचाई सुविधाओं, मुफ्त बिजली, और अत्याधुनिक सिंचाई तकनीकों के साथ कम ब्याज दर पर किसान ऋण दिया जा रहा है ताकि पंजाब कृषि उत्पादों का शीर्ष श्रेणी का उत्पादक बनने में अग्रणी हो सके। साथ ही,

राज्य में बड़े व्यापारिक घरानों और कॉर्पोरेट लॉबी को निमंत्रण देकर औद्योगिक विकास और वृद्धि सुनिश्चित की जा रही है।

- एसएडी राज्य में बेहतर आधारभूत सुविधाओं के साथ-साथ विश्व स्तरीय शिक्षण संस्थानों का निर्माण करके पंजाब के लोगों के लिए जीवन के बेहतर मानकों को सुनिश्चित करने के लिए प्रयास करती है। अपनी नीतियों और प्रशासन के माध्यम से, एसएडी पंजाब की आबादी के प्रत्येक वर्ग तक पहुंचती है।

विचार-विमर्श

पंजाब की प्रमुख राजनीतिक पार्टी शिरोमणि अकाली दल ने पंजाब की राजनीति में अहम भूमिका निभाई लेकिन आज अपने अस्तित्व के लिए संघर्ष करती दिख रही है. भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस भारत में सबसे पुरानी राजनीतिक पार्टी है जिसकी स्थापना साल 1885 में हुई. उसके करीब 35 साल बाद भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी यानी सीपीआई की स्थापना हुई. सीपीआई की स्थपाना के दो महीने बाद शिरोमणि अकाली दल का गठन हुआ.

भारतीय स्वाधीनता संग्राम का यह वो दौर था जब महात्मा गांधी आंदोलन की रीढ़ बन चुके थे. सत्याग्रह और असहयोग आंदोलन न सिर्फ अंग्रेजी शासन के खिलाफ हो रहा था बल्कि भारतीय समाज में व्याप्त कुरीतियों को समाप्त करने, शोषक जमींदारों से मुक्ति, मंदिरों में दलितों के प्रवेश और गुरुद्वारों को कुछ लोगों की मुट्ठी से छुड़ाने के लिए भी शुरू हो चुका था.[2]

सीपीआई की स्थापना रूसी क्रांति से प्रभावित थी जबकि शिरोमणि अकाली दल पर गांधी की अहिंसात्मक संघर्ष की नीति का प्रभाव था और जिस तरह से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस आंदोलन की उपज थी, उसी तरह यह पार्टी भी गुरुद्वारों में भ्रष्ट महंतों के खिलाफ हुए संघर्ष और गुरुद्वारों की मुक्ति के लिए चले आंदोलन से जन्मी थी. गुरुद्वारों का संचालन उस वक्त निजी तौर पर होता था और उनका नियंत्रण भी कुछेक महंतों के हाथ में होता था. इतिहासकार बिपिन चंद्र ने अपनी पुस्तक 'भारत का स्वाधीनता संघर्ष' में लिखा है कि केश न रखने के कारण मुगल इन महंतों को हिंदू समझते थे और इस वजह से ये महंत मुगलों के कोपभाजन होने से बचते रहे. लेकिन समय के साथ ये महंत भ्रष्ट होते गए और गुरुद्वारों में आने वाले चढ़ावे को निजी संपत्ति मान उसका दुरुपयोग करते रहे.

1920 के दशक में इन महंतों के खिलाफ सिख सुधारकों ने गांधीवादी तरीके से अभियान चलाया और न चाहते हुए भी अंग्रेज सिख गुरुद्वारा अधिनियम, 1925 लाने पर मजबूर हुए. साल 1920 में गुरुद्वारों को महंतों से आजाद कराने के लिए 175 सदस्यीय एक टास्क फोर्स का गठन किया गया जिसे शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी नाम दिया गया.

संघर्ष का नेतृत्व करने, बड़ी संख्या में स्वयंसेवकों को आंदोलन से जोड़ने और आंदोलन को सुनियोजित तरीके से चलाने के लिए 14 दिसंबर 1920 को अकाली दल का गठन हुआ जो बाद में शिरोमणि अकाली दल बन गया. बिपिन चंद्र लिखते हैं कि महंतों के खिलाफ लोगों में गुस्से की कुछ तात्कालिक वजहें भी थीं. चूंकि इन्हें ब्रिटिश हुकूमत का पूरा समर्थन मिलता था इसलिए ये महंत भी सरकार का साथ देते थे.

साल 1920 में ही दो घटनाओं ने आग में घी डालने का काम किया. पहली घटना में अमृतसर के स्वर्ण मंदिर से एक फरमान जारी हुआ जिसमें विदेशों में रहकर अंग्रेजी सरकार के खिलाफ संघर्ष कर रहे गदर आंदोलन से जुड़े क्रांतिकारियों को विद्रोही घोषित कर दिया गया और दूसरी घटना यह हुई कि साल 1919 में अमृतसर के जलियांवाला बाग में नरसंहार करने वाले जनरल डायर को सरोपा भेंट करके उन्हें सिख घोषित कर दिया गया.

आंदोलन यूं तो अहिंसक रहा लेकिन 20 फरवरी 1921 को ननकाना साहब गुरुद्वारे में प्रवेश करने की कोशिश रहे अकालियों पर गोली चलाई गई जिसमें बड़ी संख्या में लोग मारे गए. हालांकि अकाली इस गुरुद्वारे में प्रवेश करने में सफल रहे. आंदोलन को अपना समर्थन देने के लिए खुद महात्मा गांधी ननकाना साहब पहुंचे और उनके साथ मौलाना शौकत अली के अलावा कई बड़े नेताओं ने इस आंदोलन के प्रति अपनी एकजुटता प्रदर्शित की. अकाली दल और और एसजीपीसी ने असहयोग आंदोलन को समर्थन दिया और स्वतंत्रता संघर्ष में कांग्रेस और गांधी जी के साथ रहे. साल 1925 में गुरुद्वारों का नियंत्रण एसजीपीसी के हाथ में आ गया.

परिणाम

महात्मा गांधी ने आंदोलन के नेता बाबा खड़ग सिंह को अंग्रेजों द्वारा स्वर्ण मंदिर की चाबियां सौंपे जाने की घटना को अंग्रेजों से आजादी के लिए चल रहे संघर्ष में भारत की पहली जीत बताया.

करीब बीस साल तक अकाली दल और कांग्रेस मिल कर अंग्रेजों के खिलाफ संघर्ष करते रहे. 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन से पहले तक कांग्रेस और शिरोमणि अकाली दल की दोहरी सदस्यता आम बात थी. यहां तक कि बाबा खड़ग सिंह भी 1922 में अकाली दल का अध्यक्ष बनने के बाद भी पंजाब में कांग्रेस के महत्वपूर्ण नेता रहे.

सिखों की लड़ाई लड़ने वाले शिरोमणि अकाली दल ने साल 1937 में पहली बार चुनावी मैदान में कदम रखा और पंजाब में 10 सीटें हासिल कीं. साल 1947 में जब मजहब के आधार पर देश का बंटवारा हुआ तो शिरोमणि अकाली दल के तत्कालीन प्रमुख मास्टर तारा सिंह ने इसका विरोध किया. [3] पूर्व राज्यसभा सदस्य तरलोचन सिंह ने कुछ समय पहले संसद में कहा था कि यदि तारा सिंह ने विभाजन के समय पाकिस्तान में एक सिख राज्य के लिए जिन्ना के कुछ देने के बदले कुछ लेने की मंशा को खारिज न किया होता तो पूरा पंजाब पाकिस्तान में चला गया होता. दरअसल साल 1930 से 1965 तक सिख राजनीति के सर्वेसर्वा बाबा खड़ग सिंह के उत्तराधिकारी मास्टर तारा सिंह ही थे.

साल 1950 के दशक में देश भर में भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की मांग तेज हुई तो इस आंदोलन की आंच पंजाब पर भी आई. आंदोलन यहां भी चला लेकिन साल 1956 में राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिश पर जिन राज्यों की स्थापना हुई, उसमें पंजाब का नाम नहीं था. पंजाब को साल 1966 में अलग राज्य का दर्जा मिला और अगले साल हुए विधानसभा चुनाव में शिरोमणि अकाली दल के नेता गुरनाम सिंह राज्य के पहले अकाली मुख्यमंत्री बने. साल 1975 में लगे आपातकाल का सबसे पहला विरोध शिरोमणि अकाली दल की ओर से किया गया और प्रकाश सिंह बादल, गुरचरण सिंह टोहड़ा, जगदेव सिंह तलवंडी जैसे कई प्रमुख नेता गिरफ्तार किए गए थे. अकाली दल के इंदिरा गांधी से रिश्ते यहीं से बिगड़ने लगे. इंदिरा गांधी ने सत्ता में लौटने के बाद साल 1978 में बनी अकाली सरकार को भंग कर दिया.

1980 के दशक में पंजाब अलगाववाद और उग्रवाद के साये में रहा. साल 1984 में इंदिरा गांधी की हत्या के बाद स्थितियां और बिगड़ गईं. अकाली दल को भी कट्टरपंथी राजनीति का सामना करना पड़ा लेकिन उग्रवाद के खात्मे के बाद स्थितियां बदलने लगीं और शिरोमणि अकाली दल एक बार फिर मुख्य धारा की राजनीति में सक्रिय हो गई. कभी कांग्रेस के साथ रहने वाली पार्टी अब कांग्रेस की मुख्य प्रतिद्वंद्वी पार्टी हो गई और साल 1996 में भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन करके राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन में शामिल हो गई जो पिछले साल कृषि कानूनों के खिलाफ शुरू हुए किसान आंदोलन की शुरुआत तक चलता रहा.

पंजाब में शिरोमणि अकाली दल कई बार सत्ता में रही है लेकिन साल 1970 में प्रकाश सिंह बादल के मुख्यमंत्री बनने के बाद से पार्टी में पूरी सत्ता उनके परिवार के ही पास केंद्रित हो गई है. साल 1992 में शिरोमणि अकाली दल ने विधानसभा चुनाव का बहिष्कार कर दिया, लेकिन साल 1997 में बीजेपी के साथ मिलकर भारी बहुमत से सत्ता में वापसी की. तब से लेकर साल 2021 तक पार्टी ने तीन बार सरकारें बनाईं और तीनों बार प्रकाश सिंह बादल ही मुख्यमंत्री बने.

प्रकाश सिंह बादल के बेटे सुखबीर सिंह बादल पिछली सरकार में राज्य के उप मुख्यमंत्री के साथ पार्टी के अध्यक्ष भी रहे. सुखबीर सिंह बादल की पत्नी हरसिमरत कौर केंद्र में नरेंद्र मोदी सरकार में मंत्री भी थीं लेकिन पिछले साल कृषि कानूनों क विरोध में उन्होंने इस्तीफा दे दिया और अकाली दल ने एनडीए से अलग होने की भी घोषणा कर दी. हालांकि कृषि कानूनों की वापसी के बाद पार्टी के एनडीए में शामिल होने के फिर कयास लगाए जा रहे हैं लेकिन जानकारों का कहना है कि ऐसा होना फिलहाल मुश्किल दिख रहा है.

सौ साल पुरानी यह पार्टी भले ही एक क्षेत्रीय दल के रूप में ही खुद को दर्ज करा सकी लेकिन राष्ट्रीय राजनीति में भी कई मौकों पर महत्वपूर्ण भूमिका निभाई. फिलहाल परिवारवाद के संकट से जूझने के अलावा उसे कांग्रेस पार्टी के साथ साथ आम आदमी पार्टी से भी चुनौती का सामना करना पड़ रहा है. [4]

निष्कर्ष

आम तौर पर सारे पंजाब वासियों और विशेष तौर पर सिखों की सबसे पुरानी पार्टी कही जाने वाली शिरोमणि अकाली दल (एसएडी), वर्तमान दौर में अपने राजनीतिक अस्तित्व के सबसे संकटग्रस्त दौर से गुजर रही है। पंजाब में राजनीति के कई जानकारों के विचार में हालाँकि पार्टी ने 1920 में अपनी स्थापना के बाद से कई उथल-पुथल के दौर देखे हैं, लेकिन मौजूदा समय में जिस प्रकार का संकट है वह अपने आप में अभूतपूर्व है।

मौजूदा पार्टी नेतृत्व (मुख्यतया बादल परिवार) के सामने एक गंभीर चुनौती आन पड़ी है, जिसके बारे में कई लोगों का मानना है कि फिलवक्त इस संकट से निपटने के लिए वे मजबूत स्थिति में नहीं दिखते हैं। अकाली दल का सांगठनिक ढांचा अपेक्षाकृत कमजोर हुआ है और उसकी नेतृत्व वैधता दांव पर लगी हुई है। यह घटनाक्रम पार्टी के शीर्षस्थ नेताओं की नेतृत्व करने की क्षमता पर गंभीर सवाल खड़े करती है।

अकाली दल के साथ यह प्रकिया 2017 के पंजाब विधानसभा और 2019 लोकसभा चुनावों, विधानसभा उप-चुनावों के साथ-साथ शहरी एवं अर्ध-शहरी नगर निकायों, समिति और ज़िला परिषद के चुनावों में उसके खराब प्रदर्शन के साथ शुरू हो चुकी थी, भले ही भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के साथ इसका गठबंधन रहा हो।

अकाली दल के धूमिल प्रदर्शन ने इसके शीर्ष नेतृत्व के बदतर प्रबंधन कौशल की कलई खोलकर रख दी है। इसके साथ-साथ हाल के वर्षों में, संसद के भीतर तीन केंद्रीय कृषि कानूनों पर इसके समर्थन के चलते पार्टी की समस्याएं और भी अधिक बढ़ गई हैं।

पहले पहल, अकाली दल ने केंद्र में भाजपा नेतृत्व वाले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन का हिस्सा होने के नाते इस विधेयक की वकालत की और समर्थन किया था। बाद में, नरेंद्र मोदी सरकार में इसकी एकमात्र प्रतिनिधि, हरसिमरत कौर बादल को इस्तीफ़ा देना पड़ा और किसानों के विरोध प्रदर्शनों के बढ़ते दबाव को देखते हुए पार्टी ने एनडीए से अपना समर्थन वापस ले लिया।[5]

इस बात को याद किया जा सकता है कि अकाली दल जनसंघ और बाद में भाजपा के सबसे पुराने सहयोगियों में से एक रही है। लेकिन आज के दिन हालात एक ऐसे दौर में पहुँच गए हैं कि

अन्य पारंपरिक दलों के नेताओं की तरह ही अब अकाली नेता भी किसानों एवं अन्य लोगों के गुस्से के डर से आगामी विधानसभा चुनावों में समर्थन हासिल करने के लिए ग्रामीण एवं अर्ध-शहरी इलाकों का दौरा करने से बचते दिख रहे हैं।

अकाली दल को गंभीर झटका तब लगा जब सुखदेव सिंह ढींडसा, मनजिंदर सिंह सिरसा, सेवा सिंह सेखवां, रणजीत सिंह ब्रह्मपुरा सहित कई अन्य प्रमुख नेताओं ने या तो अपनी खुद की पार्टी बनाने या अन्य दलों में शामिल होने के लिए पार्टी छोड़ दी। नेताओं के इस तरह लगातार पलायन ने शीर्ष नेतृत्व के सामने मुसीबतों का अंबार खड़ा कर दिया है।

अकाली दल में वर्तमान संकट की शुरुआत को जानने के लिए 2007 से इसे देखा जा सकता है जब पार्टी के कई वरिष्ठ और टकसाली (लंबे समय से प्रमाणित) नेताओं की अनदेखी करते हुए पार्टी अध्यक्ष, सुखबीर सिंह बादल को उनके पिता प्रकाश सिंह बादल के द्वारा पार्टी नेतृत्व की कमान सौंप दी गई थी। इस घटनाक्रम ने रणजीत सिंह ब्रह्मपुरा, रतन सिंह अजनाला (पूर्व लोकसभा सदस्यों), सुखबीर बादल के चचेरे भाई और बादल सरकार में तत्कालीन वित्त मंत्री मनप्रीत सिंह बादल और राज्यसभा सांसद सुखदेव सिंह ढींडसा जैसे कई पार्टी के दिग्गजों को नाराज कर दिया था।

इन नेताओं के पार्टी से नाता तोड़ने के बाद कई मध्य-क्रम के नेताओं के इस्तीफों का दौर शुरू हो गया। इनमें से अधिकाँश नेता हाल के दिनों में भाजपा में शामिल हो गए हैं। हालाँकि कुछ पुराने नेताओं ने सक्रिय राजनीतिक जीवन से सन्यास लेने के पीछे स्वास्थ्य एवं वृद्धावस्था का हवाला दिया है, लेकिन असल बात तो कुछ और ही थी। उनमें से अधिकांश को आने वाले दिनों में अकाली दल में कोई भविष्य नहीं दिख रहा था क्योंकि 2017 विधानसभा चुनावों और उसके बाद हुए कई चुनावों में लोगों ने पार्टी को बुरी तरह से खारिज कर दिया गया था। यह सिर्फ 15 सीटें ही जीत सकी थी और इसकी जगह आम आदमी पार्टी (आप) ने सदन में मुख्य विपक्षी पार्टी का स्थान ग्रहण कर लिया था।

अकाली दल में इस निरंतर पतन और इसकी संरचना सभी स्तरों पर पूरी तरह से उजागर हो चुकी है। पार्टी के 100 वर्षों के इतिहास में यह बात भी अपनेआप में अभूतपूर्व है कि एक बेटे को उसके पिता के द्वारा ही पार्टी की कमान सौंपी गई हो।

कई वर्षों से बादल परिवार के द्वारा बड़े पैमाने पर उन नए लोगों को भर्ती करके पार्टी और सरकार पर अपनी पकड़ को मजबूत करने का काम किया गया है, जो शीर्ष नेतृत्व के प्रति अपनी पूर्ण निष्ठा भाव रखते हैं। यह सब टकसाली नेतृत्व को हाशिये पर रखने के लिए किया गया था। युवा ब्रिगेड की कमान सुखबीर सिंह बादल के बहनोई बिक्रमजीत सिंह मजीठिया के हाथों सुपुर्द कर दी गई, जो खुद 2007 चुनावों के दौरान ही सक्रिय हुए थे।

इस प्रक्रिया का नतीजा यह हुआ कि पार्टी के भीतर वरिष्ठ नेताओं सहित समझदार कार्यकर्ताओं को पूरी तरह से हाशिए पर डाल दिया गया, और उनकी जगह संदिग्ध साख रखने वाले लोगों ने ले ली। असल में देखें तो 2012 विधानसभा चुनावों में अकालियों की जीत ने नेतृत्व के संकट को टालने का ही काम किया, और जिसके परिणामस्वरूप नए नेतृत्त्व को उन चुनावों में जीत और पार्टी प्रबंधन दोनों ही मामलों में प्रबंधन कौशल का श्रेय दिया गया। उस जीत ने सरकारी मशीनरी और पार्टी के उपर बादलों के पूर्ण नियंत्रण की ओर उन्मुख किया, जिसके चलते अंततः पार्टी के भीतर कुछ ही हाथों में सत्ता का पूर्ण केन्द्रीयकरण हो गया, और पार्टी में भर्ती हुये नए रंगरूटों के द्वारा सभी स्तरों पर आतंक का विकेंद्रीकरण कर दिया गया।

सादगी के स्थान पर गुंडागर्दी की एक नई संस्कृति ने पार्टी की मूल भावना को कुम्हला दिया। अकाली दल कभी सिद्धांतों पर चलने वाली पार्टी हुआ करती थी जिसका बलिदानों का गौरवशाली इतिहास रहा है। यह भारत के सबसे पुराने क्षेत्रीय राजनीतिक दलों में से एक है जो 1920 में अस्तित्व में आ गई थी। पार्टी की मूल उत्पत्ति ही स्वतंत्रता-पूर्व भारत में दमनकारी एवं निरंकुश बर्तानवी शासन और इसी तरह की रियासतों के खिलाफ संघर्ष में हुई थी। 1975 में आपातकाल के दौरान इंदिरा गाँधी के दमनकारी शासनकाल के खिलाफ पार्टी का मोर्चा समकालीन दौर में अतुलनीय रहा है।

10 वर्षों के अकाली दल के शासन (2007-2017) के परिणामस्वरूप किसानों की विनाशकारी स्थिति, बिगडती राजकीय अर्थव्यवस्था और बढ़ते कर्ज, बढ़ते ड्रग नेटवर्क, भ्रष्टाचार के स्तरों में लगातार वृद्धि, सर्वोच्च नयायालय में हरियाणा के खिलाफ सतलुज-यमुना लिंक मामले में मिली हार, गुंडागर्दी और कुछ स्थानीय अकाली नेताओं का अहंकार, राज्य परिवहन, शराब, रेत और बजरी माफिया पर एकछत्र राज, विभिन्न स्थानों पर गुरु ग्रंथ साहिब (सिखों की पवित्र पुस्तक) की बे-अदबी (अपमान) के रूप में बढ़ती धार्मिक असहिष्णुता ने वर्तमान दौर में अकाली दल की स्थिति को बद से बदतर बना डाला है।[6]

आगामी विधान सभा चुनावों (20 फरवरी को) में अकाली दल के और भी हाशिये पर चले जाने के आसार साफ़-साफ़ नजर आ रहे हैं। पंजाब के आम लोगों का दृढ़ मत था और यकीन है कि शक्तिशाली बादल परिवार और उसके करीबी रिश्तेदार कथित तौर पर मादक पदार्थों की तस्करी, खनन और शराब माफिया, जन-विरोधी गतिविधियों, राजनीतिक प्रतिशोध इत्यादि में हाथ था। 2017 में लोकनीति द्वारा किये गये चुनावोपरांत सर्वेक्षण में भी यह बात पूरी तरह से स्पष्ट हो गई थी। यह पहली बार था कि मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार के तौर पर प्रकाश सिंह बादल की लोकप्रियता 1997 के बाद से सबसे निचले स्तर पर पहुँच गई थी।

दमनकारी शासन के खिलाफ आम लोगों के मूक विद्रोह की वजह से एक दशक तक सत्ता में बने रहने के बाद अकालियों को जबर्दस्त सत्ता विरोधी लहर का सामना करना पड़ा था। यह सत्तारूढ़ बादल कुल और उन लोगों के खिलाफ एक निजी दुश्मनी की लहर थी, जो हर स्तर पर गुंडागर्दी में शामिल थे। उन्हें ऐसे धूर्त तिकड़मबाज राजनीतिज्ञों के तौर पर देखा जाने लगा जिन्होंने अपने तुच्छ निजी स्वार्थों के लिए समूची राजनीतिक प्रक्रिया को अपहृत कर लिया था।

आम लोगों के बीच में यह धारणा घर कर गई थी कि शिरोमणि अकाली दल ने कार्यकाल की लूट को साझा करने के लिए करीबियों और विस्तारित परिवार के लोगों और मित्रों के एक निजी क्लब में तब्दील कर दिया है। संभवतः यही वजह थी

जिसके चलते बादलों और वरिष्ठ अकाली नेताओं पर पिछले विधानसभा चुनावों के दौरान कई दफा शारीरिक हमले भी हुए।

सबसे चौंका देने वाला उदाहरण उनके अपने खुद के निर्वाचन क्षेत्र लाम्बी थाट में मुख्यमंत्री जूते से हमला था, जिसमें कुछ रिपोर्टों के मुताबिक उनका चश्मा टूट गया था। इसी तरह उनके बेटे और तत्कालीन उप—मुख्यमंत्री (सुखबीर) के लाव-लश्कर पर उनके विधानसभा क्षेत्र में पथराव की घटना हुई थी।

एक अन्य घटना में, अकाली दल के एक वरिष्ठ नेता और तत्कालीन सांसद की पगड़ी निकाल दी गई थी, और तख़्त दमदमा साहिब के बाहर एक मंत्री और उनके बेटे का एक भौंडे शोरगुल में घेराव किया गया था जहाँ से उन्हें पुलिस के द्वारा बचाया गया था। ये सभी चीजें पार्टी के भविष्य के शुरूआती संकेत थे।

अकालियों, जिन्होंने हमेशा से अपने राजनीतिक एजेंडे को आगे बढ़ाने के मकसद से सिख धर्म का बेहद चतुराई से इस्तेमाल किया है, वे भी भरोसा करने वालों की नजरों में गिर गये और उन्हें गुरु ग्रंथ साहिब को अपवित्र करने और अन्य घटनाओं जिनसे उनकी धार्मिक भावनाएं आहत होती हैं के लिए जिम्मेदार माना जा रहा है। सिखों के बीच में आम लोगों को लगता है कि अकाली नेतृत्व वाली सरकार बे—अदबी मुद्दे को संबोधित न करने के लिए जिम्मेदार थी और सिख धर्म की भावनाओं का आदर करने में विफल रही है। इस वजह से, पंजाब के लोगों के बीच में अकालियों ने अपना धार्मिक आधार खो दिया है।

बेअदबी का मुद्दा कांग्रेस के काम आया, जिसने इसका इस्तेमाल राजनीतिक उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए अकाली नेतृत्व को और भी अधिक हतोत्साहित करने के लिए किया। बाद में, विधानसभा के विशेष सत्र के दौरान बेअदबी के मुद्दे पर अकाली विधायकों का न्यायाधीश रंजीत सिंह की रिपोर्ट पर चर्चा से भाग खड़े होना, सदन की कार्यवाही तक का सामना न कर पाने की स्थिति ने सार्वजनिक तौर पर इसके नेतृत्व की कमजोरी को उघाड़कर रख दिया था।

अकाली दल के शीर्ष नेतृत्व के द्वारा एक के बाद भारी भूल की जाती रही। सबसे पहले, इसने ग्रंथी को सिरसा के डेरा सच्चा सौदा प्रमुख को क्षमादान देने के लिए मजबूर किया, और बाद में आम लोगों के आक्रोश को देखते हुए अपने फैसले को रद्द कर दिया, जिसके चलते पार्टी और इसके नेतृत्व की छवि को बट्टा लगा, जिनकी आलोचना ऐसे अहम धार्मिक मुद्दों से निपटने के लिए की गई थी।

इन घटनाओं ने दिखा दिया कि अकाली नेतृत्व के द्वारा न सिर्फ अपरिपक्वता का परिचय दिया गया, बल्कि इसमें गुरुचरण सिंह तोहड़ा, जगदेव सिंह तलवंडी, लोंगोवाल आदि जैसे परिपक्व नेताओं के विचारशील सलाह का भी अभाव था।

लगता है मोदी ब्रांड वाली राजनीति के साथ अकालियों के गठबंधन ने भी हाल के दिनों में उनकी अलोकप्रियता में ब�ोत्तरी करने का काम किया है।

अकाली दल में मौजूदा संकट और इसके नेतृत्व के खिलाफ गुस्सा इसलिए भी गहरा गया है क्योंकि पिछले कई वर्षों से बादलों ने मनमाने तरीके से संगठन के भीतर लोकतांत्रिक प्रकिया को ताक पर रख दिया है। पार्टी और शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के भीतर हर एक फैसले को नियंत्रित करके बादल परिवार ने पार्टी में किसी भी अन्य नेता के लिए कोई जगह नहीं छोड़ी है।

बादलों की तानाशाही के खिलाफ पार्टी के भीतर के लोगों में भारी गुस्सा बना हुआ है। भाजपा के साथ अकाली दल के घनिष्ठ संबंधों को देखते हुए अभी भी इसे संदेहा की नजरों से देखा जाता है। तीन कृषि कानूनों के मद्दे पर पार्टी के द्वारा मोदी सरकार से किनारा कर लेने के बाद भी इसे अपन खोई हुई राजनीतिक जमीन को वापस पाने में मदद नहीं मिल सकी है। धार्मिक बेअदबी, पवित्र ग्रंथ के पन्नों को फाड़ने आदि की विभिन्न घटनाओं के चलते इसने अपने मूल पंथिक (सामुदायिक नेतृत्व) के समर्थन आधार को भी खो दिया है।

हालिया घटनाक्रम, जैसे कि बिक्रमजीत सिंह मजीठिया के खिलाफ मादक पदार्थों वाले मुद्दे से संबंधित मामला भी अकाली नेतृत्व के लिए शर्मिंदगी की स्थिति पैदा कर रहा है और कार्यकर्ताओं पर इसका मनोबल गिराने वाला प्रभाव पड़ रहा है।

कुलमिलाकर देखें तो पंजाब के मौजूदा हालात इस बात की ओर इशारा कर रहे हैं कि आने वाले चुनावों में पार्टी को एक बार फिर से बड़ी शर्मिंदगी का सामना करना पड़ सकता है। अकाली नेतृत्व को पार्टी के पतन पर आत्ममंथन करने की जरूरत है, जिसका गौरवशाली अतीत रहा है, और एक वो समय भी था जब इसके द्वारा भारत में सभी क्षेत्रीय दलों का नेतृत्त्व कर राज्यों को अधिक स्वायत्तता सुनिश्चित करने, केंद्र-राज्य संबंधों के पुनर्गठन और भारत में लोकतांत्रिक एवं धर्मनिरपेक्ष मूल्यों को मजबूत करने में अग्रणी भूमिका हुआ करती थी।[7]

संदर्भ

[1] जलाल, आयशा (1994) [पहली बार 1985 में प्रकाशित], द सोल स्पोक्समैन: जिन्ना, द मुस्लिम लीग एंड द डिमांड फॉर पाकिस्तान , कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी प्रेस, आईएसबीएन 978-0-521-45850-4

[2] जलाल, आयशा (2002), स्व और संप्रभुता: 1850 से दक्षिण एशियाई इस्लाम में व्यक्तिगत और समुदाय , रूटलेज, आईएसबीएन 978-1-134-59937-0

[3] टैलबोट, इयान (1998), पाकिस्तान: ए मॉडर्न हिस्ट्री , सेंट मार्टिन प्रेस, ISBN 978-0-312-21606-1

[4] हरजिंदर सिंह दिलगीर। सिख तवारीख । सिख यूनिवर्सिटी प्रेस, बेल्जियम, 2007। 5 खंड (पंजाबी में)

[5] हरजिंदर सिंह दिलगीर। सिख इतिहास । सिख यूनिवर्सिटी प्रेस, बेल्जियम, 2010-11। 10 खंड

[6] हरजिंदर सिंह दिलगीर। शिरोमणि अकाली दल (1920-2000) । सिख यूनिवर्सिटी प्रेस, बेल्जियम, 2001।

[7] हरजिंदर सिंह दिलगीर। नवान महान कोष (दिलगीर कोष,) । सिख यूनिवर्सिटी प्रेस, इंग्लैंड।